उत्तर प्रदेश

ई-संदेश

21 फरवरी, 2018 • वर्ष 1, अंक 5

सात दिन – सात पृष्ठ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इन्वेस्टर्स समिट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, राज्यपाल राम नाईक जी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह तथा गणमान्य निवेशकों के साथ

1045
एमओयू हुए हस्ताक्षरित

UP INVESTORS SUMMIT 2018
POWERINGNEWINDIA

4.28
लाख करोड़
के निवेश प्रस्ताव

निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का काम शुरू

संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश

UP POWERING NEW INDIA
INVESTORS SUMMIT 2018
21-22 February

पोटेन्शियल, पॉलिसी, प्लानिंग और परफॉर्मेन्स से होगी प्रोग्रेस

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मानना है कि उत्तर प्रदेश में संसाधनों और सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता है उद्योगों के अनुकूल माहौल बनाने की, ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हों और प्रदेश में खुशहाली आए। मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ के इन्दिरा गाँधी प्रतिष्ठान में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। इस बहुप्रतीक्षित इन्वेस्टर्स समिट का शुभारम्भ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने राज्यपाल श्री राम नाईक, केन्द्र तथा प्रदेश सरकार के मंत्रियों तथा देश–विदेश से आए उद्योगपतियों तथा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बड़े ही जोशपूर्ण माहौल में किया।

> ‘पोटेन्शियल’, ‘पॉलिसी’, ‘प्लानिंग’ और ‘परफॉर्मेन्स’ से ही ‘प्रोग्रेस’ आती है। योगी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ‘सुपर हिट परफॉर्मेन्स’ देने के लिए तैयार है।
>
> **–नरेन्द्र मोदी**
> प्रधानमंत्री

सर्वांगीण विकास के दृष्टिगत तेजी से कार्य कर रही है योगी सरकार

प्रधानमंत्री जी ने इस भव्य आयोजन हेतु मुख्यमंत्री जी की सराहना करते हुए कहा कि योगी सरकार प्रदेश के त्वरित विकास के दृष्टिगत तेजी से निर्णय ले रही है और आवश्यक नीतियों का निर्माण भी कर रही है। राज्य में अलग–अलग सेक्टर्स की नीतियां बनाकर काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को रोजगार सृजन से जोड़ते हुए नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं। योगी सरकार पूरी गम्भीरता से किसानों, महिलाओं, नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने का कार्य कर रही है।

एक जन्पद–एक डतपाद योजना से बदलेगी प्रदेश की अर्थव्यवस्था

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एम.एस.एम.ई.) का बहुत बड़ा योगदान है। कृषि के बाद एम.एस.एम.ई. सेक्टर में ही रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर पैदा होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखते हुए ‘एक जनपद–एक उत्पाद’ योजना शुरू की। इस योजना को ‘बैकअप पावर’ केन्द्र सरकार के स्किल इण्डिया, स्टैण्ड अप इण्डिया, स्टार्ट अप इण्डिया मिशन से मिलेगी। इस उद्योग हितकारी योजना को ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ से जोड़कर एम.एस.एम.ई. सेक्टर का कायाकल्प किया जा सकता है। ■

वर्तमान राज्य सरकार उद्यमियों के लिए ‘रेड टेप’ नहीं ‘रेड कार्पेट’ की व्यवस्था कर रही है। निवेशकों की समस्याओं का त्वरित निदान सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि उन्हें अपने उद्योग स्थापित करने में कोई दिक्कत न हो।

प्रधानमंत्री ने देश के पहले औद्योगिक पोर्टल ‘निवेश पोर्टल’ का शुभारम्भ किया। इस पोर्टल में निवेशकों को क्लियरेन्सेज़, पेमेण्ट्स इत्यादि सभी सुविधाएं ऑनलाइन मिलेंगी।

इन्वेस्टर्स समिट
के आयोजन से उत्कृष्ट राज्य बना उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री

विश्व पटल पर भारत को स्थापित करने का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। प्रदेश को विकासशील और समृद्ध बनाने के दृष्टिगत इन्वेस्टर्स समिट में एग्रो और फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, हैण्डलूम एण्ड टेक्सटाइल, एम.एस.एम.ई, आई.टी./ आई.टी.ई.एस. एण्ड स्टार्टअप, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, फिल्म, टूरिज्म, सिविल एविएशन और रिन्यूएबिल एनर्जी फोकस सेक्टर निर्धारित किए गए।

इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन के अवसर पर योगी जी ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत विभिन्न सेक्टर्स में पूर्व से स्थापित तथा नई औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए विभिन्न नीतियाँ बनाई गई हैं। सरकार का लक्ष्य आगामी तीन वर्षों में उद्योगों द्वारा 40 लाख रोजगार सृजन का है।

राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड

औद्योगिक विकास हेतु राज्य सरकार को नीतिगत रणनीति बनाये जाने हेतु सुझाव देने के लिए 'राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड' का गठन किया गया है। इस बोर्ड के माध्यम से देश के अग्रणी उद्योगपतियों का सक्रिय सहयोग प्रदेश की औद्योगिक नीतियों को एक दिशा प्रदान करने में मिल सकेगा।

बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान

प्रदेश में व्यापार और उद्योग को सुगम बनाने और विभिन्न स्वीकृतियों आदि से सम्बन्धित प्रक्रियाओं को आसान बनाने के उद्देश्य से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत बिजनेस रिफॉर्म ऐक्शन प्लान 20 विभागों द्वारा लागू कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। औद्योगिक इकाइयों से संबंधित स्वीकृतियों, अनुमोदनों, अनुमतियों तथा लाइसेन्सों की ऑन–लाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने के लिए डिजिटल क्लीयरेन्स की प्रणाली लागू की गयी है, जिसकी मॉनीटरिंग सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जा रही है।

स्टार्टअप नीति से इनोवेशन को बढ़ावा

राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट–अप नीति लागू की गयी है। यह नीति विभिन्न औद्योगिक सेक्टर्स में इनोवेशन के लिए एक मजबूत धरातल नये उद्यमियों को प्रदान करेगी। इस नीति के माध्यम से स्टार्ट–अप्स के लिए आई.आई.टी. कानपुर, बी.एच.यू. सहित प्रदेश के शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों को जोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे साइन किये गये एम.ओ.यू. की मॉनिटरिंग

प्रदेश सरकार पर्यावरण हितैषी विकास की पक्षधर है

'पावरिंग यूपी' से साकार होगा प्रधानमंत्री का 'न्यू इंडिया विजन'

"उद्योगों के विकास के लिए उत्कृष्ट परिवहन सुविधाओं का होना अत्यन्त आवश्यक है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे तथा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के माध्यम से लोगों को त्वरित आवागमन के साधन उपलब्ध होंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण भी कराया जाएगा।

उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले 'वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर' तथा 'ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर' से राज्य से माल ढुलाई के समय में बेहद कमी आएगी। ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर' के दोनों तरफ विकसित की जा रही 'अमृतसर-कोलकाता इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर' परियोजना को केन्द्रित करते हुए, उत्तर प्रदेश में 02 नेशनल इन्वेस्टमेन्ट एण्ड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स तथा इण्टीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स विकसित किए जाएंगे।

प्रदेश में विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों को वायुयान सुविधा से जोड़ने के लिए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम बनायी गयी है। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना करायी जा रही है, जिससे प्रदेश में औद्योगिक निवेश तथा नागरिक विमानन सेवाओं में वृद्धि होगी।

एमओयू क्रियान्वयन मैकेनिज्म तैयार करने में जुटे अफसर

इन्वेस्टर्स समिट सम्पन्न होने के तुरन्त बाद ही अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की टीम एमओयू के क्रियान्वयन से जुड़ी कार्यवाही में जुट गई। सभी प्राप्त एमओयू को जिले व विभागवार अलग-अलग करने के निदेर्कश दिए गए हैं। प्रस्तावित व्यवस्था में एक-एक एमओयू की लेटेस्ट अपडेट उपलब्ध होंगे। ऑनलाइन सिस्टम होने से मुख्यमंत्री जी जब जिस प्रोजेक्ट के बारे में चाहेंगे, उसकी प्रगति जान सकेंगे।

निजी क्षेत्र में निवेश का बड़ा केन्द्र बनेगा यूपी

निवेश से खुलेंगे रोजगार के द्वार

कंपनी	निवेश करोड़ रू.	संभावित रोजगार
अडाणी ग्रुप	36,450	19,300
आदित्य बिड़ला	25,000	30,000
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर	16,105	13,450
शिकारिया इंफ्रा	16,000	10,000
पावनम वाटर सल्यूशन	12,000	100
सीआईडीबी होल्डिंग	10,000	5,000
हिन्दुजा ग्रुप	10,000	1,000
रिन्यू पावर	8,000	12,000
टॉरंट पावर	6,000	5,300
एजुर पावर	6,000	3,500
एक्सपोर्ट क्लस्टर	5,000	5,00,000
एस्सेल इंफ्रा	5,000	100
स्टरलाइट ग्रिड	5,000	1,000

- 100 नंबर इमरजेंसी रिस्पांस सेवा को और सृदृढ़ करेगा महिन्द्रा समूह
- 400 गांवों में सामाजिक उत्तरदायित्व के अन्तर्गत कार्य कर रहा है बिड़ला समूह

लखनऊ में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में देश के शीर्ष उद्योगपतियों ने राज्य के विकास में हर संभव सहायता देने का वादा किया। इन उद्यमियों ने प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य का खाका खीचा। उन्होंने यूपी में जिस प्रकार से निवेश का वादा किया है, उससे अनुमान है कि यूपी में अगल तीन वर्षो में तीन लाख से अधिक रोजगार पैदा होंगे।

उद्यमियों ने न केवल उद्योग–धंधो की स्थापना पर चर्चा की, वरन् अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति भी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उद्यमियों ने कृषि, विनिर्माण, डिजिटल, सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर, आईटी, इन्फोकॉम, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्यूफैक्चरिंग इत्यादि क्षेत्रों में निवेश के साथ ही वाराणसी में हेल्थकेयर सेंटर खोलने, लखनऊ में टीसीएस के विस्तार, प्रदेश में मानव संसाधन के समुचित उपयोग करने, गांवों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, दुग्ध विकास जैसे कार्यो के लिए भी एमओयू साइन किय गये। इनसे प्रदेश में औद्योगिक विकास की नई इबारत लिखने में मदद मिलेगी।

निवेशकों को नहीं होगी यूपी में कोई दिक्कत

प्रदेश में उद्यमियों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रदेश सरकार उद्यमियों के साथ प्रति क्षण खड़ी रहेगी। उत्तर प्रदेश उद्योगपतियों के लिए सर्वथा उपयुक्त प्रदेश है क्योंकि यहां सड़क, सुरक्षा, बिजली, पानी तथा अन्य सभी चीजें सुलभ हैं, जो एक उद्यम के लिए आवश्यक होती हैं। प्रदेश सरकार ने निवेशकों के लिए मित्रवत नीतियां बनाई हैं तथा उनकी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया है।

- नमामि गंगे को सफल बनाने में सहायता करेगा रिलायंस समूह
- इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्यूफैक्चरिंग प्लान्ट लगायेगा महिन्द्रा समूह
- सोशल सिक्योरिटी क्षेत्र में काम का विस्तार करेगा आदित्य बिड़ला समूह

सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश

सार्वजनिक उपक्रम	निवेश करोड़ रु.
एकेआईडीसी	35000
डीएफसीसीआईएल	16105.31
टीएचडीसीआईएल	12000
भेल	12000
मथुरा रिफाइनरी विस्तार	8700
डीएमआईसी डीसी	5000
नेविलागिनाइटिस	5000
आईओसीएल	4000
गेल विस्तार	1200
एचपीसीएल	700
सीसीआईएल	505
इफ्को	350

सरकारी कंपनियां करेंगी 90 हजार करोड़ निवेश

उत्तर प्रदेश में बदले माहौल का ही असर रहास कि न केवल निजी कंपनियां, बल्कि पब्लिक सेक्टर की बड़ी कंपनियां भी प्रदेश में निवेश को लेकर उत्साहित नजर आई। पब्लिक सेक्अर की कंपनियों ने 90,000 करोड़ रूपये से अधिक के एमओयू साइन करके प्रदेश में बदलते औद्योगिक माहौल पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी है। पब्लिक सेक्टर की कंपनियों ने राज्य सरकार के साथ जो एमओयू साइन किए हैं, उसका प्रभाव यूपी में आने वाले 2–3 वर्षो के भीतर स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ेगा।

यूपी का बजट लगभग 4.28 लाख करोड़ रूपये का है और इतने के ही एमओयू साइन हुए हैं। सरकार का लक्ष्य अगले तीन साल में 40 लाख नई नौकरियां प्रदान करने का है।

पावर सेक्टर में होगा एक लाख करोड़ का निवेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रदेश के हर घर को बिजली पहुंचाने की योजना को निवेशकों ने भरपूर सहयोग प्रदान करते हुए प्रदेश में बिजली उत्पादन को बढ़ाने तथा ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए एक लाख करोड़ रूपये से अधिक के निवेश का वादा किया है। सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति का ऐलान किया है, जिसके अन्तर्गत निवेशकों को कई तरह की रियायतें प्रदान की गई हैं। इस नई सौर ऊर्जा नीति के प्रति निवेशकों के भारी उत्साह के परिणामस्वरूप सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 63,000 करोड़ रूपये से अधिक के एमओयू साइन हुए हैं।

2 लाख करोड़ की सड़के बनेंगी यूपी में

समिट में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यूपी को केवल जमीन देनी है, केन्द्र सरकार इस साल यूपी में दो लाख करोड़ रूपये की सड़कें बनाकर दे देगा। इसके अतिरिक्त दिल्ली से मेरठ के मध्य विकसित हाई–वे भी यूपी को मिलने जा रहा है।

भारी निवेश से प्रदेश बनेगा आर्थिक महाशक्ति

मुकेश अंबानी
अध्यक्ष, रिलायंस इंडस्ट्रीज
10 हजार करोड़

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना देश को सर्वोत्तम बनाना है, तो हम सबको मिलकर यूपी को सर्वोत्तम बनाने के लिए प्रयास करने होंगे। यूपी बढ़ेगा तभी भारत ग्लोबल पावर बनेगा। रिलायंस अगले तीन साल में यूपी में 10 हजार करोड़ रूपये निवेश करेगा। इससे एक लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। यूपी को योगी आदित्यनाथ जी जैसा कर्मयोगी सीएम मिला है। हम यूपी के विकास के लिए योगीजी को पूरा सहयोग देंगे।

गौतम अडानी
अध्यक्ष, अडानी ग्रुप
35 हजार करोड़

बिना यूपी के इंडिया का ग्रोथ नहीं हो सकता है। भारत विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति तभी बनेगा, जब यूपी आर्थिक तौर आगे बढ़ेगा। अडानी समूह ऊर्जा, लॉजिस्टिक, ड्राईपोर्ट, वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेटेड एग्री हब, 1000 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट, हाईवोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन और विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने में अगले तीन वर्षो में 35 हजार करोड़ निवेश करेगा।

उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने और विश्व में भारत का मान बढ़ाने के लिए यूपी में निवेश करें। विगत दो माह में यूपी सरकार से जो सहयोग मिला है, उसके बाद यही कहूँगा कि उद्यमी यहां आएं और खुले दिल से निवेश करें। योगी सरकार और उसके अधिकारी काफी सतर्क हैं और एमओयू हाने के बाद निवेश के हर पहलू को बारीकी से देख रहे हैं। जी नेटवर्क ग्रुप यूपी में 18750 करोड़ रूपये निवेश करेगा।

सुभाष चंद्रा
अध्यक्ष, एस्सेल समूह
18.75 हजार करोड़

ईज आफ डूईंग बिजनेस में यूपी सातवें स्थान पर आ गया है। इससे कई क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर पैदा हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री फ्रेंडली माहौल के साथ भारी मात्रा में मानव संसाधन उपलब्ध है। यहां उद्योगों में विस्तार देखकर काफी खुशी हो रही है। यूपी में आदित्य बिड़ला ग्रुप नंबर वन इन्वेस्टर है। आदित्य बिड़ला ग्रुप अगले पाँच वर्षो में यूपी में 25 हजार करोड़ रूपये का निवेश करेगा।

कुमार मंगलम बिड़ला
अध्यक्ष, आदित्य बिड़ला समूह
25 हजार करोड़

आनन्द महिन्द्रा
अध्यक्ष, महिन्द्रा ग्रुप
200 करोड़

यूपी की तुलना दूसरे राज्यों से नही करनी चाहिए, बल्कि दूसरे देशों से करने का लक्ष्य होना चाहिए। महिन्द्रा यूपी में इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में दो सौ करोड़ रूपये का निवेश करेगा। वाराणसी में इलेक्ट्रिल व्हीकल मैन्यूफैक्चरिंग प्ल्याण्ट लगाया जाएगा। क्लब महिन्द्रा गोरखपुर में धर्मिक पर्यटन के अनुकूल रिजार्ट बनाएगा। महिन्द्रा ग्रुप सामाजिक कार्यो में भी योगदान देगा।

एन. चंद्रशेखरन
अध्यक्ष, टाटा संस
बनेगा नया कैंपस

टीसीएस लखनऊ में कारोबार को और मजबूती देगी। नया कैंपस बनेगा जहां तीस हजार लोगों को रखा जा सकेगा। यूपी के चहुंमुखी विकास के लिए टाटा समूह प्रदेश सरकार के सहयोग से कार्य करेगा। वाराणसी में आईटी सेंटर खोला जायेगा। प्रदेश में बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं तथा प्रचुर मात्रा में मैनपावर सुगमता से उपलब्ध है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर होने से कार्य करना आसान हुआ है।

यूपी में कानून व्यवस्था तथा एजूकेशन सेक्टर में काफी सुधार हुआ है। इससे प्रदेश का माहौल बदला है और राज्य के विकास की राह आसान हुई है। यूपी में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं। सीआईआई द्वारा चार कौशल विकास केंद्र इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में स्थापित किये जायेंगे। उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराया जायेगा। वाराणसी में हेल्थ केयर पर कार्य किया जायेगा।

शोभना कामिनेनी
अध्यक्ष, सीआईआई
होगा स्किल डेवलपमेंट

यूपी में निवेश का माहौल बना है और यूपी के लिए एक बड़ा टर्निंग प्वाइंट है। इससे न केवल निवेश बढ़ेगा, बल्कि देश में एक अच्छा मैसेज भी जायेगा। नयी निवेश नीति से निवेश का नया प्लेटफार्म तैयार हुआ है। यूपी में डेयरी सेक्टर में काफी संभावनाएं हैं। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार के साथ मिलकर यूपी ट्रेवल मार्ट का आयेजन किया जायेगा। स्टार्टअप इंडिया में फिक्की पूरा सहयोग करेगा।

रशेस शाह
अध्यक्ष, फिक्की
स्टार्टअप पर जोर

पार्टनर देश यूपी को हर क्षेत्र में देंगे सहयोग

जापान करेगा वाटर ट्रीटमेंट ऊर्जा तथा कृषि में निवेश

जापान की औद्योगिक व आर्थिक प्रगति में 30 वर्ष पूर्व शुरू हुई 'वन विलेज वन प्रोडक्ट' योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसी तर्ज पर यूपी 'वन डिस्ट्रक्ट वन प्रोडक्ट' के माध्यम से विकास की राह पर चल पड़ा है। पार्टनर देश जापान के प्रतिनिधियों ने पारंपरिक, सौर व पुनर्चक्रित ऊर्जा, सड़क व पुल निर्माण, ऑटोमोबाइल, फूड प्रासेसिंग तथा बौद्ध पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपार संभावनाएं तलाशने पर जोर दिया।

जापानी कंपनी मियाची ने वाटर ट्रीटमेंट और सौर ऊर्जा से बिजली बनाने के क्षेत्र में काम करने की इच्छा जताई तो मित्सुबिशी हिटाची ने हवा की गुणवत्ता में सुधार पर बल देते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार के क्षेत्र में कार्य करने का इरादा व्यक्त किया। जापानकी मिटसुई केमिकल्स एग्रो तथा कोनोआईकेई कम्पनियों ने 'फसलोत्पादन–फूड सप्लाई चेन' की स्थापना एवं रखरखाव, अन्ना तथा डेयरी क्षेत्र में निवेश की इच्छा व्यक्त की है।

दुग्ध उत्पादन बढ़ाएगा नीदरलैंड

भारत में औसतन एक गाय सात लीटर दुग्ध देती है तो नीदरलैंड में लगभग 45 लीटर। इसका कारण है कि नीदरलैंड में गायों के आहार तथा उनकी बेहतर देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इन क्षेत्रों में काम करके यूपी में भी दुग्ध उत्पाद के क्षेत्र में इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त किये जा सकते है। नीदरलैंड की कंपनी डी ह्यूज और ट्रो ने इस क्षेत्र में कार्य करने की रूचि व्यक्त की। नीदरलैंड से आए प्रतिनिधिमण्डल ने डेयरी फार्म, दूध में वैल्यू ऐडेड यूनिट, पशु आहार, डेयरी संचालन में नई तकनीकों व उपकरणों के प्रयोग तथा कैटल फार्मा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की इच्छा व्यक्त की।

आवासीय योजनाओं में निवेश को तैयार फिनलैंड

फिनलैंड के राजदूत अपने देश की नौ कंपनियों के साथ समिट में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि फिनलैंड यूपी के विकास के लिए उत्सुक है।

फिनलैंड की एलिमेटिक प्री–कास्ट टेक्नोलॉजी कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि आज के युग में मकान बनाने का काम प्री–कास्ट तकनीक आधारित हो चुका है। इस तरह निर्माण कराने से लागत में 50 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है।इसके अतिरिक्त निर्माण सामग्री में लगभग 7 प्रतिशत तथा मानव श्रम तथा निर्माण में लगने वाले समय में भी 50 प्रतिशत तक की बचत होती है। यूपी में अफोर्डेबल हाउसिंग की सरकारी नीति की विशेषताओं के दृष्टिगत फिनलैंड की इस प्रमुख कंपनी ने यहां कार्य कने की इच्छा जताई।

चार्जर और प्लग निर्माण करने वाली सालकॉम इंडिया कंपनी ने यूपी में निवेश के माध्यम से सालाना एक अरब चार्जर उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त फिनलैंड की मिरका इंडिया तथा अन्य प्रतिनिधि कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी यूपी में निवेश की इच्छा व्यक्त की।

- फिनलैंड स्मार्ट सिटी में मदद करेगा
- गोमतीन दीम ेंम छलीप ालनक ेि लए जापान करेगा सहयोग
- लेजर तकनीक करेगी खेती में मदद

- कोरिया की तकनीक से गांवों में बनेंगे छोटे कोल्ड स्टोरज
- फल और सब्जियों के पांच–दस हजार बोरे रखने की होगी क्षामता

प्रदेश को मिले तोहफे

- फतेहपुर और झांसी में रेल कारखाना
- दुधवा और कतर्निया घाट के मध्य हेरिटेज ट्रेन
- रायबरेली रेल कोच फैक्ट्री की क्षमतावृद्धि
- गोरखपुर का लोकोशेड इलेक्ट्रिक शेड में बदलेगा
- वाराणसी में अमूल दूध की डेरी
- ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर
- नोएडा – सैमसंग द्वारा फ्रिज की फैक्ट्री
- नोएडा – 2024 तक तैयार होगा जेवर एयरपोर्ट, दिल्ली को भी लाभ
- लखनऊ और जेवर एयरपोर्ट में बनेंगे अन्तर्राष्ट्रीय हब और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
- इलाहाबाद से जुड़ेंगे लखनऊ, पटना, भोपाल, कोलकाता, नागपुर और बंगलुरू
- जल्द शुरू होगा कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट
- आगरा से झांसी–महोबा को जोड़ते हुए चित्रकूट तक एक्सप्रेस–वे
- कानपुर आर्डिनेन्स फैक्ट्री हेतु कार्ययोजना
- बुन्देलखण्ड डिफेन्स कॉरिडोर बनेगा, जिसमें झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ और कानपुर में भी निवेश होगा
- प्लास्टिक कचरे से फ्यूल आयल की रिफाइनरी वाराणसी व गाजियाबाद में बनेगी

केवल आर्थिक ही नहीं, भावनात्मक निवेश भी है आवश्यक : राष्ट्रपति

दो दिनों तक चलने वाले इस औद्योगिक महाकुंभ की शोभा उस समय और भी अधिक बढ़ गई, जब महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी स्वयं इस महाआयोजन के समापन समारोह में पहुंचे।

भावनात्मक निवेश से बढ़ेगा लगाव

इस अवसर पर अपने उद्बोधन में उन्होंने इन्वेस्टर्स समिट के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देते हुए कहा कि केवल आर्थिक निवेश से काम नहीं चलेगा, भावनात्मक निवेश भी आवश्यक है। भावनात्मक निवेश होगा तो आर्थिक निवेश की सफलता से कोई रोक नहीं सकेगा। भावनात्मक निवेश से प्रदेश के प्रति लोगों का लगाव बढ़ेगा।

प्रदेश में है अर्थ शक्ति की संभावनाएं

श्री कोविंद ने का कि उत्तर प्रदेश में अर्थ शक्ति की प्रचुर संभावनाएं विद्यमान हैं। खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद तथा पशुपालन में अनेक संभावनाएं हैं। चमड़ा उद्योग, कालीन उद्योग, वस्त्र उद्योग, पीतल, जरी और कांच के साथ ही लकड़ी के उत्पाद में ब्राडिंग व मार्केटिंग के माध्यम से अच्छा प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है।

उ.प्र. में देश की सबसे बड़ी श्रमशक्ति

देश की सबसे बड़ी श्रमशक्ति उत्तर प्रदेश में है। निश्चित तौर पर समिट के माध्यम से किए गए निवेशों के बाद प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

20 लाख को मिलेगा रोजगार

प्रदेश में चार लाख 28 हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों से राज्य आर्थिक रूप से सुदढ़ होगा। समिट के माध्यम से प्रदश में अप्रत्यक्ष तौर पर 20 लाख लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा।

डिफेंस कॉरिडोर में होगा एक लाख करोड़ का निवेश

2000 करोड़ रूपये से खुलेंगे 2000 पोर्टेबल पेटेल पंप

सिंगापुर की तर्ज पर विकसित होंगे नोएडा और ग्रेटर नोएडा

4 लाख करोड़ और निवेश करना चाहते हैं उद्यमी

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए, निदेशक श्री अनुज कुमार झा द्वारा प्रकाशित. सम्पादक : सुहेल वहीद अंसारी